Statement

Commodity (Name)	No. of sample analysed	No. of samples exceeding prescribed limit
1. Vegetables	231	1
2. Fruits	181	1
3. Cereals	74	6*
4. Pulses	103	2*
5. Vegetable oils	52	..
6. Dairy products	7	6
TOTAL	648	16

*33 samples of cereals and 31 samples of pulses also showed presence of DDT for which no tolerance limit has been prescribed. However, the level was below the detectable level in most of rice and wheat flour samples,

"बीस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये राज्यों को केन्द्र के अनुदेश"

212. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के संबंध में गुजरात और अन्य राज्यों में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कौन-कौन से राज्य बीस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं; और इसके क्या कारण हैं तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) जो राज्य बीस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में पिछड़े रहे हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार ने क्या-क्या अनुदेश दिए हैं और ये कब दिए हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मासिक प्रगति रिपोर्ट में शामिल किए गए सूत्र/मदों के बारे में अप्रैल, 88 से फरवरी, 89 तक की अवधि के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 150 अनुषंग संख्या 7] इस विवरण पत्र में प्रत्येक राज्य का सूत्र-वार और मदवार निष्पादन भी दर्शाया गया है । कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा बताई गई कठिनाइयां सामान्यतः (1) अपर्याप्त आधारी संरचनात्मक सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था (2) भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयां जिनमें वनभूमि शामिल है, (3) निधियों की कमी (4) निर्माण सामग्री की कमी और (5) सहायता की दूसरी किस्त आदि के लिए पुराने लाभ-भोगियों की पहचान करने में कठिनाई आदि है ।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जब कमी दिखाई देती है, तभी यह मंत्रालय मामले के संबंधित राज्य के साथ तत्काल उठाता

है ताकि कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। संबंधित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी संबंधित राज्यों का दौरा करते हैं ताकि कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

इस वर्ष, इस मंत्रालय में पहली बार एक क्रांतिक दल का गठन किया ताकि यह दल बोध सूत्री कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए समस्याओं का पता लगाकर और उनके समाधान के लिए सुझाव देकर गहन समीक्षा कर सके। क्रांतिक दल ने केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श भी किया। क्रांतिक दल की रिपोर्ट केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच मार्च, 89 में परिचालित की गई थी ताकि उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

Targets of arms exports

213. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to answer to Starred Question 161 given in the Rajya Sabha on the 7th March, 1989 and state:

(a) what are the targets of arms export fixed by Government for 1989-90; and

(b) whether Government propose to acquire sophisticated technology for arms manufacture so as to be able to stand in competitive international arms market, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) Government have not fixed any targets for arms exports for the year 1989-90. Defence Public Sector Undertakings, however, fixed their own export targets.

(b) There is no proposal with the Government to acquire technology for arms manufacture for being competitive in international arms market.

Manufacture of low cost computer

214. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Starred Question 100 given in the Rajya Sabha on the 28th Februray, 1989 and state:

(a) whether 80 proposals for designing the low cost computers have been received by Government; and

(b if so, by when the final decision in this regard is likely to be taken and what would be the capacity for production of low cost computers in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Government has received 80 proposals from various manufacturers for the production of low cost computers against preliminary enquiry floated by Department of Electronics. Out of these, 40 are composite proposals involving production of all the sub-systems of personal computers. However, these proposals are not for designing the low cost personal computer.

(b) On the basis of the information provided in the said proposals, a detailed plan for the standardisation of design and centralised procurement of material etc. for the production of such computers is being worked out.

Meeting of the Indo-Chinese sub-Committee on Science and Technology

215. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: